शोध पत्र

Dec.-09—Jan.-2010

# अंग्रेजों की कृषि नीति

* नाईक नारायण ज्ञानोबा

*मु. हाटकरवाडी पो. रामपूरी ( बु. ) ता. मानवत जि. परभणी.

डलहौजी के समय तक भारत पर अंग्रेजी राजसत्ता प्रस्थापित हुई थी। आर्थिक सत्ता विस्तार के साथ-साथ राजनैतिक सत्ता का विस्तार भी किया गया। राजनैतिक सत्ता हस्तगत करने पर भी अंग्रेजों का एकमात्र लक्ष्य था कि, भारत का आर्थिक शोषण करना। जब शोषण करना है तो उसके लिये शासन भी जरुरी था। जब राजनैतिक वर्चस्व प्रस्थापित होने के बाद उन्होने संवैधानिक भारत का आर्थिक दोहन किया। आर्थिक लाभ कमाने का मुल स्त्रोत कृषि था। अंग्रेजों ने अपना ध्यान कृषि पर दिया, और कृषि से मिलने वाला भू-राजस्व महत्वपूर्ण था।

भारत कृषिप्रधान देश होने के नाते (कारण) भारत में सबसे ज्यादा कर भू-राजस्व से ही मिलता था। इसलिए अंग्रेजो ने कृषि पर ध्यान केंद्रित किया। बंगाल पर अधिकार करने से उन्होंने द्वैध्द शासन पध्दती लागू कि थी। धीरे-धीरे उसका विकास किया गया। कार्नवालिस के काल मे स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू कि थी, थॉम्स मनरो ने रैयतवाडी प्रथा लागू कर दि थी। बाद में १८०१ में संयुक्त प्रांत में महालवाडी प्रथा का प्रचलन किया गया। जो की पुरा गॉंव या महाल भू-राजस्व अदायगी का उत्तरदायी था। ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ती के लिये कृषि व्यापारीकरण किया गया। इस आर्थिक क्षेत्र का विस्तार के साथ-साथ उन्होंने राजनैतिक विस्तार करने का प्रारंभ किया। ब्रिटीशों ने अर्थसत्ता को मजबूत करने के लिये राजसत्ता का विस्तार करना प्रारंभ किया। इस विस्तार करने के लिये चाहे अलग-अलग तरह के और विचार प्रणाली के गवर्नर भारत मे भेजे थे लेकीन उद्देश मात्र था भारत का आर्थिक शोषण और भारत का शोषण उपहार, वेतन, भत्ते और व्यापार करके भारत इतना गरिब बना दिया की, भारतीय नर-नारी को दो वक्त की रोटी के लिये विवश होना पडा। बहूत सारे लोग भूखमरी के बली हो गए।

### कृषि का वाणिज्यीकरण या व्यापारिकरण :

नए भूमि सम्बधों को लागू करने तथा निर्धारित धन की अदायगी की भू-राजस्व व्यवस्था का एक परिणाम यह हूआ की ग्रामीण कृषि का पूराना उद्देश अर्थात गांव के उपभोग के लिये उत्पादन का स्थान अब बाजार के लिये उत्पादन ने ले लिया।

उत्पादन और उत्पादों का अब एक नये अर्थ विक्री के उद्देशों से निर्धारन किया जाना था और इस प्रकार उनका स्वरुप हि बदल गया।[१] नई प्रणाली के अन्तर्गत किसान मुख्यतः बाजार के लिये उत्पादन करने लगे, जिसके लिये उन्हें ब्रिटीश शासन के अन्तर्गत परिवहन के निरन्तर विकसित हो रहे साधनों तथा व्यावसायिक पूँजी लगाने के लिये अवसर उपलब्ध होने लगे। वे ऐसा मुख्यतः अधिकतम नकद धन प्राप्त करने के उद्देश्य से करते थे, जिससे वे बहूत ऊँची दरों पर निर्धारित भू-राजस्व की रकम को राज्य को अदा कर सकें और महाजनों के दावों को पूरा कर सके, जिनके चंगुल में वे अनेक कारणों फँसे हूए थे।[२]

उन्नीसवी सदी के उत्तरार्ध तक देश के विदेश व्यापार, जहाजरानी एवं बीमे के कारोबार पर वस्तुतः ब्रिटीश व्यापारिक प्रतिष्ठांनो का पूर्ण नियंत्रण हो चुका था। अतः बढते निर्यात से मिलनेवाले लाभांश का बडा हिस्सा विदेशी फर्मे हडप लेती थी और वह 'विदेशी रिसावों' के रुप में देश के बाहर चला जाता था।

इसका एक गौण किंतू फिर भी अच्छा-खासा भाग भारतीय व्यापारियों एवं महाजनों को जाता था। ये वे दलाल थे जो किसानों को आवश्यक अग्रीम राशी देकर उत्पादन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते थे। ऐसी पेशगियों की आवश्यकता भी लगान के बोझ से जूडी हुई थी, और इस प्रकार जैसा की हाल ही में गोरखपूर जिले के गन्ना उत्पादन के बारे मे व्यष्टिस्तरीय अध्ययन से ज्ञात होता है, वहॉं पूंजीवाद पेठ पहले से स्थापित हूआ। भू-स्वामी एवं साहूकार के शोषण की संरचना को सुदृढ करने में सहायक हुई (चीनी मिले स्थानीय जमींदारें एवं महाजनों को किसानों से गन्ना एकत्र करने के लिये ठेकेदारों के रुप में नियुक्त करती थी)।[३]

निर्यात करने वाली बडी फर्मे एवं चतुर भारतीय व्यापारी और साहूकार तो घट हूए मुल्यों से भी उसी प्रकार लाभ उठा सकते थे

जिस प्रकार बडे मुल्यों से किंतू उत्पादन पूँजी-निवेश अथवा नये व्यापार मे बहूत खतरा था। किसी भी किसान के पास जब थोडा धन जमा हो जाता था तो वह व्यापार, साहूकारी अथवा अपनी जमीन में बंटाई पर देने की और रुख करता था, और इस प्रकार स्वयं वास्तविक पूँजीवादी कृषि न करके उत्पादन का समस्त खतरा परजीवी रुप से दुसरों पर डाल देता था।

जहां तक बहूसंख्यांक निर्धन किसानों का प्रश्न था, वे बाध्य होकर वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया मे पडे थे क्योंकि राजस्व एवं भूमि का भाडा चूकाने के लिये नकद रुपयों कि आवश्यकता होती थी। कोयंबटूर के किसानों ने एक बार एक अंग्रेज जिलाधिश से कहां था कि, कपास की खेती केवल इस कारण कर रहे है कि, वे कपास को खा नही सकते। यदी वे अन्न उगाते तो उसे खा डालते और फिर लगान भरने को पैसा कहां से आता।[४] अब वे आधे पेट रहते है, किंतू लगान को चूका सकते है।

राजस्व एवं लगान के दबाव के कारण खेती का रुख गरीबो के खाद्यानों जैसे ज्वार, बाजरा या दालों से हटकर नगदी एवं गेहू जैसी अधिक मुल्य दिलाने वाली फसलों की और हो गयी जिसके कारण प्रायः अकाल के समय संकट उत्पन्न हो जाया करता था।[५]

**जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त :**

ब्रिटीशपूर्व भारत में जमींदारी प्रथा भारत में विद्यमान थी। तैमुर वंश के धनी सम्राट अकबर ने जमींदारी प्रथा को निर्माण किया था। इस समय जो जमींदार थे उन्हे सिर्फ लगान वसूल करने का अधिकार था। उसके बदले उसे निश्चित रकम अपने पास रखने का अधिकार था। भारत मे जब ब्रिटीश शासन प्रस्थापित हुआ, और भू-सुधार के नाम एक नई प्रणाली का सृजन किया गया। उसे जमींदारी पध्दती कहां गया। नया बंदोबस्त करने के लिये अंग्रेजों ने सबसे पहली चीज यह की कि अनुसंधान के साथ विलायत की जमींदारी प्रथा को अंग्रेजों ने हिंदुस्तान मे चलाया। १७९३ इ.स. मे लार्ड कार्नवालीस ने बंगाल, बिहार और उडिसा मे जो पक्का बंदोबस्त किया था,[६] उसकी यह विशेषता थी।

आगे चलकर यह बंदोबस्त उत्तरी हिंदुस्तान मे लागू कर दिया गया। उस समय के जमींदार वास्तव मे राजाओं कि नियुक्ती के लिये मालगुजार किसान या हाकिम होते थे। मालगुजारी के लिए उन्हे कमीशन मिलता था। सरकारी तौर से कमीशन दर २ २/१ फीसदी होनी थी। हालांकी वास्तव मे इससे ज्यादा दर भी लिया जाता था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को अपने जमींदारी क्षेत्रों का पूर्णस्वामी घोषित कर दिया।[७] ब्रिटीश समर्थक यह तर्क देते है की अंग्रेजो ने उस समय की भू-परम्परा को न जानते हूए इस प्रथा का आरम्भ किया। परंतु यह तो एक बहाणा मात्र है। तथ्य तो यह है की कार्नवालीस को उस समय इस बात का पूर्ण ज्ञान था की वह क्या कर रहा है। किसान जो पहले भू-स्वामी थे, अब केवल पट्टेदार बनकर रह गये, जिन्हे जमींदार की इच्छा पर कभी भी हटाया जा सकता था। उस समय किसान कुल मिलाकर जितनी मालगुजारी देते थे, उसका १०/११ भाग जमींदारों से लेना तय हुआ। बाकी १/११ जमींदारों के लिये छोड दिया गया।[८] उस समय ये शर्ते जमींदारो और किसानों के लिए बहुत कडी थी और सरकार को उनसे बहुत फायदा था। बंगाल में जमींदारों को कुल मिलाकर ३० लाख पौंड (लगभग ३ करोड रुपए) लगुजारी देनी पडती थी। वहां जो वसुली होती थी, उससे यह रकम बहुत ज्यादा थी। कुछ पूराने ढंग के जमींदार अपनी परम्परा निभाते रहे, कठीनाई के समय वे किसानों से मुरव्वत करते थे और उन्हे कुछ छूट दे देते थे। ऐसा करने पर इन जमींदारों की रियासत तुरंत ही निलाम पर चढा दि जाती थी। इन पूराने ढंग से जमींदारों की बहुत सी करुण कथाएँ है।[९]

वे समझते थे की किसानों की देखभाल करना उनका कर्तव्य है, लेकीन मालगुजारी न भर पाने पर अंग्रेजों ने निर्दयता पूर्वक उन्हें जमीन से अलग कर दिया। उनकी रियासते खरीदने के लिए एक नए ढंग के लालची साहूकार आ गए।

सरकारी माल गुजारी चुका देने पर अपने जेबे भरने में उन्हें किसी तरह का आगा पिछा नही था। पक्के बंदोबस्त का उद्देश्य ही यही था कि इस तरह के सज्जन जमींदार माल गुजारी का काम संभाले। उनका एक नया वर्ग बन गया था।[१०] १८०२ इ.स. के भिरनापूर के कलेक्टर ने कहां था।

"जमीन को बेचने और जब करने के कानून से थोडेही दिनों मे बंगाल के बहुत से बडे बडे जमींदार तबाह हो गये। किसी देश या काल मे इतने थोडे दिनों मे भूमि व्यवस्था में कही भी इतना बडा परिवर्तन नही किया गया जितना बंगाल में।"[११] हिंदुस्तान की उलझी हुई व्यवस्था कंपनी के नौकरों के लिए पहले एक बंद पुस्तक के समान थी वे जमीन के मालिकों की तलाश करने लगे आगे चलकर मालुम हुआ कि इन जमींदारों मे से ज्यादातर लोक ऐसे है, जो जमीन के मालिक थे ही नही। पहले उन्हे विलायती धन का जमींदार समझ लिया गया था।[१२]

रजनी पाम दत्त ने इस मत को अस्विकार किया है। उनका कहना है की, उस समय के कागजपत्रों को देखने से अच्छी तरह मालुम हो जाता है की, लार्ड कार्नवालीस और इस काम मे लगे हुए दुसरे लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि वे जमींदारो का एक नया वर्ग बना रहे है। किस उद्देश्य से वे ऐसा कर रहे है यह भी वे अच्छी तरह जानते थे। पक्का जमींदारी बंदोबस्त करने का मतलब यह था की, अंग्रेजी ढंग के जमींदारों का एक नया वर्ग तैयार किया जाए, जो अंग्रेजी राज का सामाजिक बन जाए। अंग्रेज जानते थे की, वे संख्या मे थोडे है और उन्हे एक बहुत बडी आबादी पर राज करना है।[१३]

**रैयतवाडी प्रथा :**

रैयत का अर्थ हैं 'किसान' (जनता) और सरकार तथा कृषक के बीच सीधा बन्दोबस्त रैयतवाडी प्रथा के नाम से कहा जाता है। यह प्रथा बम्बई, मद्रास (कुछ हिस्सों को छोडकर) और पंजाब तथा कुछ भागों में भारत के कुल इलाके के ५१ प्रतिशत भाग पर प्रचलित थी। प्रारंभ में यह बन्दोबस्त वार्षिक या ५ अथवा १० वर्ष के लिए होना था यद्यपि बाद में २० से ४० तक होने लगा। कृषक को भूस्वामी तब तक निकाल नहीं सकता था, जब तक कि वह निर्धारित मालगुजारी देता रहता।[१४] ब्रिटीश लोगों व्दारा लागू की गई दुसरी राजस्व व्यवस्था थी, जिसे सर्वप्रथम थॉमस मनरों और कैप्टन रोड व्दारा बारामहल जिले में १७९२ इ.स. सन में लागू कि थी।[१५] १८०७ इ.स. में मनरों ने कहां था कि हमेशा के लिए इसी ढंग का बंदोबस्त होना चाहिए, १८२० इ.स. में उन्होने मद्रास के गवर्नर की हैसियत से सुबे अधिकांश पर इसे लागू कर दिया। यह ढांचा ब्रिटीश भारत के दुसरे इलाकों पर भी लागू किया गया और अब करीब-करीब अंग्रेजी राज की आधी जमीन में इसी तरह का बंदोबस्त है।[१६]

इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ थी, १. कृषकों के भू-राजस्व का व्यक्तिगत रुप से निर्धारण, २. खेतों की पैमाईश औ कृषि उत्पादन का आकलन ३. उपज के ५५ प्रतिशत भाग को सरकार व्दारा भू-राजस्व के रुप में निर्धारीत किया गया।[१७] इस प्रथा के अंतर्गत भूमि पैमाईश दोषपूर्ण थी, कृषि उत्पादन का आकलन गलत था। भू-राजस्व की दर बहुत अधिक थी। वेंकट सुब्बैय्या ने इस सम्बध ा में ठीक ही टिप्पणी करते हूए लिखा है कि, "इस भू-राजस्व व्यवस्था (रैयतवाडी व्यवस्था) का वास्तविक क्रियान्वयन निराशा की एक दुखद दास्तान है।"[१८]

उपसंहार : इस तरह जमींदारी प्रथा के साथ-साथ यह प्रथा अस्थायी और अन्यायपूर्ण थी जो की, करों का बोझ कृषक के उपर था इसलिए वह अपना गांव छोडकर जाते थे। जो उन्हे पकडकर जबरन कृषि करने कराने लगाते थे यह एक शोषण के हद के भी बाहर था। विश्व में अपना उपनिवेशवाद स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का आर्थिक शोषण करना प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने अपना प्रभूत्व दिर्घ समय तक स्थापित करने के लिए अपनी कृषि निती के माध्यम से शोषण करना आरंभ किया।

इस कारणवश हिंदुस्तान में कृषि का निर्धन हो गया। इस भारतीय कृषि जो परम्परागत स्थिती थी। उन स्थिती को और बढते हुए भू-राजस्व नीति ने कृषि मजदूरों की संख्या में बढती हुई। धन का दोहन होता गया। और भारतीय नागरिक गरीब बन गया। इस अलग-अलग प्रथा ने हिंदुस्तान के जनमानस पर प्रतिकुल परिणाम हुआ।

## सन्दर्भ ग्रन्थ

१. विवेक अग्निहोत्री "भारतीय इतिहास" खण्ड पृ.क्र. ८५ २. वही, पृ.क्र. ८५ ३. सुमित सरकार, "आधुनिक भारत" पृ.क्र. ४६ ४. सुमित सरकार, "आधुनिक भारत" पृ.क्र. ५० ५. वही, पृ.क्र. ५० ६. रजनी पामदत्त "आज का भारत"- अनुवादक रामविलास शर्मा पृ.क्र.२२३ ७. विवेक अग्निहोत्री "भारतीय इतिहास" पृ.क्र. ७६ ८. रजनी पामदत्त "आज का भारत"- अनुवादक रामविलास शर्मा पृ.क्र.२२३ ९. वही, पृ.क्र.२२३ १०. रजनी पामदत्त "आज का भारत"- अनुवादक रामविलास शर्मा पृ.क्र.२२४ ११. वही, पृ.क्र.२२४ १२. वही, पृ.क्र.२२४ १३. वही, पृ.क्र.२२४ १४. सुरेंद्रनाथ गुप्त "सोने की चिडीया और लुटेरे अंग्रेज" पृ.क्र. ८० १५. विवेक अग्निहोत्री "भारत का इतिहास" खण्ड-स, पृ.क्र. ८१ १६. रजनी पामदत्त "आज का भारत" अनुवादक रामविलास शर्मा पृ.क्र. २२६ १७. विवेक अग्निहोत्री "भारतीय इतिहास" खण्ड-स, पृ.क्र. ८१ १८. वही, पृ.क्र. ८१